(b) The details are as under:—

Bodghat		Narmada Sagar
Land (hectares)	13783	91348
Population	9460	86000 (Approx.)
Villages	42	254
No. of Trees	28,00,000	1,35,000
Estimated amount for Compensation	6·53	90.31

(c) Bodhghat Hydel Project is already approved by the Planning Commission and is scheduled to be commissioned by the year 1991-92 as reported by the Government of Madhya Pradesh. However, active construction is held up as the project is yet to be cleared by the Government of India under the Forest Conservation Act, 1980.

Narmadasagar Project was considered acceptable by the Technical Advisory Committee of Planning Commission in its meeting held on 22-3-1984. However, final clearance is still awaited from the Planning Commission due to want of clearance from the environmental angle from the Government of India.

(d) and (e) The Government of Madhya Pradesh have reported that local people have expressed their willingness for construction of Bodhghat Project. However, certain people have expressed their opinion both in favour and against this project.

There have also been some press reports opposing the construction of the Narmada Sagar Project by certain groups as the Project will disturb the ecology and environment of the basin for which adequate steps are being proposed to be taken during project implementation so as to minimise the ecological and environmental deterioration.

सोयाबीन इत्यादि का उत्पादन

1207. **श्री राम चन्द्र विकल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोयाबीन मूंगफली तथा कोको के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी नयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उत्पादकों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, जो 1984-85 में शुरू की गई थी, 1986–87 के दौरान सोयाबीन और मूंगफली सहित तिलहनों के विकास केलिये 17 राज्यों में चल रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्यों को बीज, पौध संरक्षण, फार्म उपकरण राइजोबियम कल्चर के उत्पादन आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आदानो के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध है। यह परियोजना खेती की उन्नत विधियों के प्रदर्शन के लिये भी सहायता मुहैया करती है।

किसानों में कोको की खेती की उन्नत विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिये केरल तथा कर्नाटक में कोको के विकास के लिये एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अतर्गत उत्पाद के फार्म स्तर के परिसंस्करण की बेहतर विधियां अपनाने के बारे में किसानों को जानकारी देने की व्यवस्था भी की गई है। इस योजना में प्रदर्शन भूखण्डों को तैयार करने तथा उनका रखरखाव करने, सहकारी/किसानों संघों को ड्रायरों की सप्लाई करने और चूहों पर काबू पाने के लिये चूहेदानियों एवं चूहे मार दवाइयों के वितरण की व्यवस्था भी है ?

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये राज सहायता

1208. **श्री रामसिंह भाई पातलीया भाई राठवा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :